दंडकारण्य परियोजना कोरापुट, उड़ीसा में अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी किया जाना

731. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलकानगिरी जिला कोरापुट, उड़ीसा के दंडकारण्य परियोजना पुनर्वास कमचारी संघ ने अपनी सेवाओं को नियमित किये जाने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अनगिनत अभ्यावेदन भेजे हैं किन्तु परियोजना के गरीब शरणार्थी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है हालांकि वे 10–15 या इससे भी अधिक वर्षों से नियमित कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इन गरीब शरणार्थी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) दण्डकारण्य परियोजना के गैर मस्टर-रोल कामगार अपनी सेवा को नियमित करने के बारे में अपना मामला जनवरी, 1983 में उच्चतम न्यायालय में ले गये। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 5–1–1988 के अपने आदेश द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण में भेजने का निदेश दिया। श्रम मंत्रालय द्वारा मामले को 23–3–1988 को औद्योगिक न्यायाधिकरण, भुवनेश्वर भेज दिया गया। इसलिए मामला अभी न्यायाधीन है।

Disparity in pay scales of social workers in Pondicherry hospitals

732. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a proposal for the removal of disparity in the pay scales of social workers in hospitals of the Union Territory of Pondicherry vis-a-vis to their counterparts in G.B. Pant Hospital, R. M. Lohia Hospital, etc. is under consideration.

(b) whether Government have since received clarifications from the Pondicherry Administration on this question as sought for; and

(c) if so, whether a decision has been taken to remove the said disparity and if not, how long it will take to take a decision in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) to (c) The Government of India have received a request regarding removal of disparity in the pay scales of social workers of hospitals of UT of Pondicherry. The matter is under examination in consultation with all concerned.

Problem of sea-erosion in Orissa

733. KUMARI SUSHILA TIRIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Central Government are aware that Orissa is facing the problem of sea-erosion;

(b) if so, the details of estimated loss incurred by the State Government as a result thereof and the quantum of Central assistance granted during the last three years on this account;

(c) whether Central Government have received any request from Orissa Government for enhancement of the assistance amount; and

(d) if so, what action is being taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) No scheme has been received from the Government of Orissa for anti-sea erosion works.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.